Business Bhaskar (Hindi) 28-2-13.

आर्थिक सर्वे में चीनी उद्योग के डिकंट्रोल की वकालत

रंगराजन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से नियंत्रण हटाने पर जोर

बिजनेस भास्कर • नई दिल्ली

आर्थिक सर्वेक्षण में रंगराजन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप अत्यधिक नियंत्रणों में बंधे चीनी उद्योग को चरणबद्ध तरीके से नियंत्रण मुक्त करने का सुझाव दिया गया है। सर्वे के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ी चीनी उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन इस उद्योग में नीतिगत स्थिरता की कमी और अनायास बदलाव जैसी समस्या रहती है। डिकंट्रोल की भूमिका बनाते हुए सर्वे में कहा गया है कि देश में चीनी उद्योग पर अत्यधिक नियंत्रण है और मूल्यगत हस्तक्षेप के कारण उत्पादन में लगातार उतार-चढ़ाव आता है। सरकार को तभी किसी तरह का दखल करना चाहिए, जब यह एकमात्र विकल्प बचे। निर्यात पर प्रतिबंध और नियंत्रणकारी पाबंदियों के बजाय न्यूनतम शुल्क व्यवस्था के जरिये घरेलू मूल्य में स्थिरता लाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

चीनी उद्योग के डिकंट्रोल पर लंबे अरसे से बहस हो रही है। सर्वे के अनुसार इस मसले पर नितांत रूप से आर्थिक आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाजार शक्तियों की भूमिका बढ़ने से ही बेहतर मूल्य निर्धारण हो सकेगा और सभी पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। रंगराजन कमेटी की सिफारिशों की चर्चा करते हुए सर्वे में कहा गया कि स्थिर नीतिगत सुधार चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने चाहिए। वित्तीय पहलू को इन सुधारों के बीच में नहीं लाना चाहिए। रंगराजन कमेटी ने केन रिजर्वेशन क्षेत्र, मिलों के बीच न्यूनतम दूरी, लेवी चीनी व्यवस्था खत्म करने की सिफारिशें की हैं। कमेटी के अनुसार राज्यों को रियायत देकर खुले बाजार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए चीनी खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। कमेटी ने खुले बाजार में बिक्री के लिए कोटा व्यवस्था और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की है।